

transmitters at Mercare (Coorg) and Karwar respectively.

The implementation of these schemes will depend on the approval of the revised Plan, availability of financial resources and relative priorities.

2. As regards television, setting up of a full-fledged TV centre at Bangalore and Programme Production Centre at Gulbarga have been approved for implementation.

### अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

2977. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जनवरी, 1981 में आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिये फिल्म समारोह निदेशालय ने कितनी धनराशि मांगी है ; और

(ख) मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री ( कुमारी कुमुदबेन . एम० जोशी ) :

(क) 53.58 लाख रुपये ।

(ख) 50 लाख रुपये ।

### Rural Electrification in Tribal Area of Orissa

2978. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) total number of villages in tribal areas of the Orissa State so far electrified and programmes for the current financial year by REC scheme sanctioned by his Ministry;

(b) the villages selected by the State Government for electrification under the normal schemes of the State in tribal areas for the years 1979-80 and 1980-81; and

3041 LS.—3.

(c) the reasons for delay in implementation of electrification schemes in tribal areas of that State, if any?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Up to 31st March, 1980, 4,344 villages in the tribal areas of Orissa had been electrified. During the year, 1980-81 535 additional villages in the tribal sub-plan area have been programmed for electrification, out of which 515 villages are likely to be electrified under REC Schemes.

(b) During 1979-80, 170 new villages were electrified in the tribal areas under the State Electricity Board's own resources. The programme for 1980-81 under the Board's Normal Development Programme is electrification of 70 villages.

(c) There are several reasons for delay in implementation of electrification schemes in the tribal areas of Orissa. The villages in the tribal areas are sparsely populated and are mostly scattered in small groups of a few hutments, and hence, there is no demand for street lights/domestic connections. There is also poor response from the consumers in these areas for energisation of pumpsets. These result in the State Electricity Board not being able to draw further instalments of loan from REC, which are released on the basis of progress achieved according to the programmed construction schedule.

### Supply of Mineral Oil by Kuwait

2979. SHRI KESHO RAO PARDHI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Kuwait has agreed to supply mineral oil to India and if so, the basis thereof; and

(b) the quantity and value of the oil to be supplied by Kuwait to India and the number of instalments in

which it will be supplied and the time by which first instalment is likely to be received?

**THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. C. SETHI):** (a) and (b). Yes, Sir. It would not be in the public interest to divulge any details of the agreement.

राजस्थान में विद्युत् उत्पादन और उस की मांग

2980. **आचार्य भगवान देव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में अब तक कुल कितना विद्युत् उत्पादन हुआ ;

(ख) वहां बिजली की मांग कितनी है ;

(ग) क्या विद्युत् उत्पादन के मामले में राजस्थान को आत्म-निर्भर बनाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री विक्रम महाजब ) :  
(क) राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित विद्युत् केन्द्रों का अप्रैल से नवम्बर 1980 का कुल ऊर्जा उत्पादन 1244 मिलियन यूनिट है ।

(ख) फिलहाल राजस्थान की मासिक ऊर्जा मांग लगभग 480 से 450 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है ।

(ग) और (घ). राज्य में विद्युत् की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं । इन उपायों में निम्नलिखित शामिल है :—

(i) राज्य में नई उत्पादन क्षमता को चालू करना । राज्य में फिलहाल निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं । नीचे दिखाई गई समय अवधि में इन से लाभ प्राप्त होंगे :—

क्रम सं०	स्कीम का नाम	लाभ प्राप्ति	
		1980-85 के दौरान (मेगावाट)	1985-90 के दौरान (मेगावाट)
1	2	3	4
1	माहो (जल विद्युत्)	140	—
2	कोटा (ताप विद्युत्)	220	—
3	अनूपगढ़ नहर (जल विद्युत्)	—	9
4	कोटा विस्तार (ताप विद्युत्)	—	420
5	देहर विस्तार (जल विद्युत्)* (राज्य का हिस्सा)	66	—
6	पौंग विस्तार (जल विद्युत्)* (राज्य का हिस्सा)	70.2	—
<b>जोड़ :</b>		<b>496.2</b>	<b>429</b>

\*ये अन्तर्राज्यीय परियोजनाएं हैं जिनमें राजस्थान भी भाग ले रहा है